



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274493
CG-DL-E-14072026-274493

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446]
No. 446]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

पंजाब नैशनल बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2026

एफ. सं. HRDD/POL/OSR/(F) .— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब नैशनल बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात और केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, के पत्र संख्या 4/2/1/2022-आईआर, दिनांक 13 मार्च, 2024 के अनुसरण में किए गए या लोपित के संबंध में, 1 नवंबर, 2022 से तथा आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि तक, पंजाब नैशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 को अतिरिक्त संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

- (1) इन विनियमों को पंजाब नैशनल बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पंजाब नैशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (इसके बाद जिन्हें उक्त विनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के, विनियम 3 में, खंड (एफ) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(एफ) चिकित्सा सुविधाओं तथा छुट्टी किराया रियायत के प्रयोजन हेतु किसी अधिकारी कर्मचारी के संबंध में 'परिवार' का अर्थ होगा -

- (i) अधिकारी कर्मचारी का पति/पत्नी ;
- (ii) पूर्णतः आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चों और विधिक रूप से गोद लिए गए बच्चों सहित) ;
- (iii) पूर्णतः आश्रित शारीरिक या मानसिक रूप से चालीस प्रतिशत अथवा उससे अधिक दिव्यांगता वाले भाई या बहन;
- (iv) विधवा पुत्रियां और आश्रित तलाकशुदा या परित्यक्त पुत्रियां ;
- (v) बहनें, जिनमें अविवाहित या तलाकशुदा या परित्यक्त या पति से विलग या विधवा बहनें सम्मिलित हैं ; और
- (vi) कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित माता-पिता :

बशर्ते कि शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के मामले में, उनकी आयु पर ध्यान दिए बिना, उन्हें विवाह के पश्चात भी आश्रित माना जाएगा, बशर्ते ये आश्रित के लिए आय मानदंडों पूरा करते हों।

स्पष्टीकरण 1.— "पूर्ण रूप से आश्रित परिवार के सदस्य" से अभिप्राय परिवार के ऐसे सदस्य से होगा जिसकी मासिक आय ₹ 18,000/- से अधिक न हो और यदि माता-पिता में से किसी एक की मासिक आय ₹ 18,000/- से अधिक है या माता-पिता दोनों की कुल मासिक आय ₹ 18,000/- से अधिक है, तो माता-पिता दोनों को अधिकारी कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2.— चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योजना और अवकाश किराया रियायत के प्रयोजनों के लिए, सभी अधिकारियों, हेतु आश्रित पिता, माता, ससुर, सास में से किन्हीं दो को कवर किया जाएगा। अधिकारी के पास एक कैलेंडर वर्ष में एक बार आश्रितों में से किसी एक या दोनों को प्रतिस्थापित करने का विकल्प होगा।

स्पष्टीकरण 3.— यह परिभाषा 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी तथा कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए, चिकित्सा बीमा योजना या पॉलिसी के प्रयोजन हेतु, आश्रितों की संशोधित मासिक आय मानदंड 1 नवंबर, 2024" से प्रभावी होंगे।

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में,—

(ए) उप-विनियम (7) के स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाएगा ;

(बी) उप-विनियम (9) और (10) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(9) 1 नवंबर, 2022 को एवं से प्रभावी, प्रत्येक ग्रेड के सापेक्ष विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे:

(ए) शीर्ष कार्यपालक संवर्ग

वेतनमान VIII = ₹ 253000 - 9000/4 - 289000

वेतनमान VII = ₹ 156500 - 4340/4 - 173860

वेतनमान VI = ₹140500 - 4000/4 - 156500

(बी) वरिष्ठ प्रबंधन संवर्ग

वेतनमान V = ₹120940 - 3360/2 - 127660 - 3680/2 - 135020

वेतनमान IV = ₹102300 - 2980/4 - 114220 - 3360/2 - 120940

(सी) मध्यम प्रबंधन संवर्ग

वेतनमान III = ₹ 85920-2680/5- 99320 - 2980/2 - 105280

वेतनमान II = ₹64820-2340/1 - 67160 -2680/10 - 93960

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन संवर्ग

वेतनमान I = ₹48480-2000/7- 62480-2340/2-67160-2680/7-85920.

स्पष्टीकरण.- प्रत्येक अधिकारी जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 को प्रभावी वेतनमानों से विनियमित होने वाले हैं को 1 नवंबर, 2022 से इस उप-विनियम में निर्धारित वेतनमान में चरण- दर -चरण आधार पर संबंधित वेतनमानों में पहले चरण से आगे के अनुरूप चरणों में, नियत किया जाएगा और वेतन वृद्धियां, निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, सामान्य रूप से वार्षिकी की तिथि पर होंगी।

(10) उप-विनियम (1) से (9) की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी ग्रेडों में सेवारत अधिकारी रखना आवश्यक है।

(11) 1 नवम्बर, 2012 को या से प्रभावी अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते का भुगतान किया जाएगा:

वेतनमान I - III - मूल वेतन का 7.75 प्रतिशत एवं उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV - V - मूल वेतन का 10 प्रतिशत एवं उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI - VII - मूल वेतन का 11 प्रतिशत एवं उस पर लागू महंगाई भत्ता

(12) 1 नवम्बर, 2017 को या से प्रभावी, अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते का भुगतान किया जाएगा:

वेतनमान I - III - मूल वेतन का 16.40 प्रतिशत एवं उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV - V - मूल वेतन का 19 प्रतिशत एवं उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI - VIII - मूल वेतन का 20 प्रतिशत एवं उस पर लागू महंगाई भत्ता

बशर्ते कि वेतनमान VIII के अधिकारी दिनांक 31.03.2020 को या से विशेष भत्ते के लिए पात्र होंगे।

(13) 1 नवंबर, 2022 को या से प्रभावी, अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते का भुगतान किया जाएगा:

वेतनमान I - मूल वेतन का 26.50 प्रतिशत एवं उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान II - III - मूल वेतन का 28.30 प्रतिशत एवं उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV – V - मूल वेतन का 30.50 प्रतिशत एवं उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI - VII - मूल वेतन का 31.50 प्रतिशत एवं उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VIII - मूल वेतन का 28.30 प्रतिशत एवं उस पर लागू महंगाई भत्ता

उप-विनियम (11), (12) और (13) में संदर्भित विशेष भत्ता और उस पर लागू महंगाई भत्ता, अधिवार्षिकता लाभों जैसे परिभाषित अंशदान योजना (नई पेंशन स्कीम) सहित, भविष्य निधि एवं उपादान के लिए संगणित नहीं होगा।

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में , -

(ए) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

“(1) विनियमन 4 के उप-विनियम (9) के प्रावधानों के अधीन, 1 नवंबर, 2022 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन वेतन वृद्धियां प्रदान की जाएगी, यथा: -

(ए) विनियम 4 के उप-विनियम (9) में वर्णित निर्धारित वेतनमानों में निर्दिष्ट वेतन वृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन, वार्षिक आधार पर उपार्जित होंगी और देय होने की माह की पहली तिथि को प्रदान की जाएगी;

(बी) वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारी को अपने वेतनमान में अधिकतम स्तर पर तक पहुंचने के एक वर्ष बाद, अगले उच्चतर वेतनमान में गतिरोध वेतन वृद्धि सहित अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी, जो उनकी दक्षता को पार करने से नीचे दिए गए खंड (सी) में निर्दिष्ट है;

(सी) कनिष्ठ प्रबंधन संवर्ग वेतनमान I के अधिकारी, जो उच्चतर स्केल के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के पश्चात खंड (ख) के अनुसार मध्यम प्रबंधन संवर्ग स्केल II के वेतनमान में पहुँच गए हैं, सेवा के प्रत्येक दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात सात गतिरोध वेतन वृद्धि के पात्र होंगे, जिनमें से प्रथम दो वेतन वृद्धियाँ ₹ 2680/- तथा अगले पांच वेतन ₹ 2980/- प्रति वेतन होंगे।

बशर्ते कि अधिकारी पांचवीं गतिरोध वेतन वृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, छठी गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा:

बशर्ते आगे कि अधिकारी पांचवीं गतिरोध वेतन वृद्धि जारी होने के चार वर्ष पश्चात अथवा 1 नवंबर, 2022 को, जो भी बाद में हो, सातवीं गतिरोध वेतन वृद्धि हेतु पात्र होगा या;

(डी) मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान II के अधिकारी, जो खंड (ख) के अनुसार उच्चतर वेतनमान की अधिकता पर पहुंचने के पश्चात् मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान III के वेतनमान में पहुँच गए हैं, सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए ₹ 2980/- की सात गतिरोध वेतन वृद्धियों के लिए पात्र होंगे

बशर्ते कि अधिकारी पांचवीं गतिरोध वेतन वृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, छठी गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा:

बशर्ते आगे कि अधिकारी पांचवीं गतिरोध वेतन वृद्धि जारी होने के चार वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, सातवीं गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा;

(ई) वास्तविक मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान III में अधिकारी, अर्थात् वे जो मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान III में भर्ती या पदोन्नत हुए हैं, वे वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के पश्चात् प्रत्येक दो वर्ष की पूर्ण की गई सेवा के पश्चात् आठ गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे जिनमें की प्रथम चार गतिरोध वेतन वृद्धियां ₹ 2980/- की होंगी तथा अगली चार गतिरोध वेतन वृद्धियां ₹ 3360/- होगी।

बशर्ते कि अधिकारी छठी गतिरोध वेतन वृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, सातवीं गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा।

बशर्ते आगे कि अधिकारी छठी गतिरोध वेतन वृद्धि जारी होने के चार वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, आठवीं गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए भी पात्र होगा ;

(एफ़) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान IV के अधिकारी, वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के पश्चात्, सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए पांच गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से प्रथम गतिरोध वेतन वृद्धि ₹ ₹ 3360/- की होगी तथा अगली चार गतिरोध वेतन वृद्धियां प्रत्येक ₹ ₹ 3680/- की होगी

बशर्ते कि अधिकारी दूसरी गतिरोध वेतन वृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, तीसरी गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा :

बशर्ते आगे कि अधिकारी दूसरी गतिरोध वेतन वृद्धि जारी होने के चार वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, अतिरिक्त चौथी गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए भी पात्र होगा :

बशर्ते यह भी कि अधिकारी दूसरी गतिरोध वेतन वृद्धि जारी होने के छह वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, पांचवीं गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए भी पात्र होगा ;

(जी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान V के अधिकारी वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के प्रत्येक दो वर्ष पश्चात् ₹ 4000/- की चार गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे :

बशर्ते कि अधिकारी वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के चार वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, दूसरी गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा :

बशर्ते आगे कि अधिकारी वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के छह वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, तीसरी गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा :

बशर्ते यह भी कि अधिकारी वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के आठ वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो चौथी गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए भी पात्र होगा;

(जी) शीर्ष प्रबंधन ग्रेड वेतनमान VI के अधिकारी वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के पश्चात् सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए तीन गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से प्रथम दो गतिरोध वेतन वृद्धियां ₹ 4000/- प्रत्येक की होंगी तथा तीसरी गतिरोध वेतन वृद्धि ₹ 4340/- की होगी:

बशर्ते कि जो अधिकारी पहले ही अधिकतम वेतनमान सीमा तक पहुंच गए हैं, वे वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, ₹ 4000/- की पहली गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा।:

बशर्ते आगे कि जो अधिकारी पहले ही अधिकतम वेतनमान सीमा तक पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के चार वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवंबर, 2022 को जो भी बाद में हो, ₹ 4000/- की द्वितीय गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा:

बशर्ते यह भी कि जो अधिकारी पहले ही अधिकतम वेतनमान सीमा तक पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान या अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के छह वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, ₹ 4340/- की तीसरी गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा ;

(i) शीर्ष प्रबंधन ग्रेड वेतनमान VII के अधिकारी, वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के पश्चात् सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए ₹ 4340/- की तीन गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि जो अधिकारी पहले ही अधिकतम वेतनमान सीमा तक पहुंच चुका है, वह वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, प्रथम गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा :

बशर्ते आगे कि जो अधिकारी पहले ही अधिकतम वेतनमान सीमा तक पहुंच चुका है, वह वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के चार वर्ष पश्चात अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा :

बशर्ते यह भी कि जो अधिकारी पहले ही अधिकतम वेतनमान सीमा तक पहुंच चुके हैं, वह वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के छह वर्ष पश्चात अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, तीसरी गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे ।

नोट: इस उप-विनियम के खंड (क) से (झ) में यथाउल्लिखित वेतन वृद्धि उस अधिकारी को नहीं दी जाएगी जो पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है।

स्पष्टीकरण-- इस उप -विनियम के अंतर्गत अगले उच्चतर वेतनमान में ऐसी वेतन वृद्धि प्रदान करना पदोन्नति नहीं माना जाएगा तथा अधिकारियों के विशेषाधिकार, अनुलाभ, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व उनके मूल पदों के अनुसार जारी रहेंगे। "

(बी) उप-विनियम (2) में , -

(i) स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे, यथा:-

“बशर्ते कि 1 नवंबर, 2022 को एवं से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा के भाग II (भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा -II) को पूर्ण करने वाले अधिकारी जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन बैंकर्स परीक्षा या भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा के भाग I को पूर्ण करने पर मिलने वाली एक वेतन वृद्धि के अतिरिक्त उनके वेतनमान में दो वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते आगे कि जो अधिकारी 1 नवंबर, 2022 को बैंक में सेवारत थे तथा पहले ही भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा या भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा II पूर्ण कर चुके हैं, वे 1 नवंबर, 2022 से या भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा या भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा II उत्तीर्ण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दूसरे अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामले में यदि कोई अधिकारी 8 मार्च 2024 तक वेतनमान की अधिकतम सीमा (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का जूनियर एसोसिएट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रमाणित एसोसिएट के मामले में) पर पहुंचने के पश्चात, या वेतनमान के अधिकतम सीमा से एक स्तर कम [भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा (भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा II के मामले में) पर

पहुंचने के बाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का जूनियर एसोसिएट / इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रमाणित एसोसिएट -I या सीएआईआईबी (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रमाणित एसोसिएट II) पहले ही अर्जित कर लिया है या अर्जित करने वाला है, तथा उसने ऐसी अर्हता प्राप्त करने पर अन्यथा पात्र हो, किन्तु वेतन वृद्धि प्राप्त न हुई हो तो, उन कार्मिकों के वेतनमान में प्रदान करने के लिए कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई हो, ऐसे मामलों में गतिरोध वेतन वृद्धि एक वर्ष या दो वर्ष, जैसा भी मामला हो, आगे बढ़ाई जा सकती है।

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (एच) के पश्चात् और नोट से पूर्व, निम्नलिखित खंड को सम्मिलित किया जाएगा, यथा:-

“(i) 1 नवंबर, 2022 को या से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक योग्यता वेतन की मात्रा निम्नलिखित तालिका में यथानिर्दिष्ट के अनुसार संशोधित होगी, यथा :-

तालिका

वे कर्मचारी जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का जूनियर एसोसिएट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का सर्टिफाइड एसोसिएट पार्ट I उत्तीर्ण किया हो ।	वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् प्रति माह ₹ 1370/-
वे कर्मचारी जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) के दोनों भाग या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ के प्रमाणित एसोसिएट -II) के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हो।	(क) वेतनमान की उच्चतम सीमा पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् ₹ 1370/-; प्रति माह (ख) वेतनमान की उच्चतम सीमा पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात् ₹ 3425/-; प्रति माह तथा (ग) वेतनमान की उच्चतम सीमा पर पहुंचने के तीन वर्ष पश्चात् ₹ 5480/-: प्रति माह

बशर्ते वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के पश्चात् इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (दोनों में से कोई एक या दोनों भाग) की अर्हता प्राप्त करने वाले अधिकारी कर्मचारी को ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तिथि से व्यावसायिक अर्हता, वेतन की प्रथम किस्त प्रदान की जाएगी तथा व्यावसायिक अर्हता वेतन की बाद की किस्तों को व्यावसायिक अर्हता वेतन की पहली किस्त की तिथि के संदर्भ में जारी किया जाएगा।

बशर्ते आगे कि 1 नवंबर, 2022 को या से वेतनमान VIII में कार्यरत किसी अधिकारी कर्मचारी को कोई व्यावसायिक योग्यता भत्ता देय नहीं होगा;

(iii) नोट में, खंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड सम्मिलित किए जाएंगे यथा:-

(vi) वे अधिकारी जो 1 नवंबर 2022 को बैंक में सेवारत थे तथा जिन्होंने पूर्व में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रमाणित एसोसिएट -I) या भारतीय बैंकर्स

संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रमाणित एसोसिएट II) पूर्ण कर लिया है एवं व्यावसायिक अर्हता वेतन-II प्राप्त कर रहे हैं, वे व्यावसायिक अर्हता वेतन-II जारी होने के एक वर्ष पश्चात अथवा 1 नवंबर, 2022 से, जो भी बाद में हो, व्यावसायिक अर्हता वेतन-III के लिए पात्र होंगे।

(vii) वे अधिकारी जिन्होंने ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट (भारतीय बैंकर्स

संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा -I) या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रमाणित एसोसिएट (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रमाणित एसोसिएट -II) पूर्ण कर ली है तथा 1 नवंबर 2022 को या उससे पूर्व वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंच गए हैं और 1 नवंबर, 2022 को या उससे पहले प्रथम गतिरोध वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं की है, वे 1 नवंबर, 2022 को या से व्यावसायिक अर्हता वेतन-I के लिए पात्र होंगे एवं व्यावसायिक अर्हता वेतन की अगली किस्त इस खंड के अंतर्गत व्यावसायिक अर्हता वेतन I जारी करने की तिथि के संदर्भ में होगी।

(सी) उप-विनियम (3) में,—

(i) खंड (जी) के पश्चात के नोट का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (एच) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(i) 1 नवंबर, 2022 को एवं से, अन्य बातें समान होने पर, मकान किराया भत्ते के साथ निर्धारित व्यक्तिगत वेतन निम्नलिखित दरों पर होगा तथा सेवा की पूरी अवधि के लिए समान बना रहेगा: -

तालिका

वेतन वृद्धि घटक (₹)	वेतन वृद्धि घटकों पर 1 नवंबर, 2022 को महंगाई भत्ता (₹)	कुल देय स्थायी वैयक्तिक वेतन जहां बैंक की आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है (₹)
(1)	(2)	(3)
2680	200	2880
2980	222	3202
3360	250	3610
3680	274	3954
4000	298	4298
4340	323	4663
9000	669	9669.

टिप्पणी:

(i) इस उप-विनियम के खंड (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच) और (आई) में तालिका के कॉलम (3) के

- अंतर्गत यथानिर्दिष्ट, नियत वैयक्तिक भत्ता या नियत वैयक्तिक वेतन उन अधिकारी कर्मचारियों को देय होगा, जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।
- (ii) मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के लिए नियत वैयक्तिक भत्ता या नियत वैयक्तिक वेतन, खंड (i) के अंतर्गत तालिका के कॉलम (1) और (2) में निर्दिष्ट कुल राशि होगी तथा जब संबंधित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) और (9) में यथानिर्दिष्ट प्रासंगिक वेतनमान की अंतिम वेतन वृद्धि अर्जित करने पर प्राप्त मकान किराया भत्ता होगा।
- (iii) केवल वे अधिकारी जो 1 नवम्बर, 1993 को या उससे पूर्व बैंक में सेवारत हों, वे अपने नियोजित वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् नियत वैयक्तिक वेतन के लिए पात्र होंगे।
- (iv) 1 नवंबर 1999 को एवं से, नियत वैयक्तिक वेतन जारी करने के कारण उप विनियम (2) में स्पष्टीकरण के खंड (सी) के अनुसार व्यावसायिक अर्हता वेतन जारी करने की अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

बशर्ते कि जहां व्यावसायिक अर्हता वेतन की कोई किस्त, जो पूर्ववर्ती उपबंधों के कारण एक वर्ष के लिए आगे बढ़ गई है तथा 1 नवम्बर, 1999 को या उसके पश्चात् जारी होने वाली है, वह अधिकारी को इसी तिथि से जारी की जाएगी तथा व्यावसायिक अर्हता वेतन की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, 1 नवम्बर, 2000 को जारी की जाएगी।

(v) नियत वैयक्तिक भत्ता या नियत वैयक्तिक वेतन का वेतन वृद्धि घटक, अधिवर्षिता लाभ के लिए रैंक किया जाएगा।

(vi) कोई अधिकारी, जिसने खंड (ए) के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धि अर्जित की है, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात्, इस उप-विनियम के खंड (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच) और (आई) में यथाउल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ता या नियत वैयक्तिक वेतन की मात्रा प्राप्त करेगा।

5. उक्त विनियमों के विनियम 21 में,—

(ए) उप-विनियम (7) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उप-विनियम को सम्मिलित किया जाएगा, यथा:-

“(8) 1 नवंबर, 2022 को एवं से,—

(ए) महंगाई भत्ता सूचकांक के प्रति प्रतिशत बिंदु के वेतन का 1 प्रतिशत देय होगा ;

(बी) औद्योगिक कामगारों के लिए आधार वर्ष 2016=100.01% अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(सीपीआई) कि तिमाही औसत में 123.03 अंकों से अधिक की वृद्धि या गिरावट के प्रत्येक परिवर्तन के लिए उपरोक्त तरीके से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। सीपीआई 2016 के प्रत्येक द्वितीय दशमलव स्थान में 123.03 अंकों से अधिक परिवर्तन के लिए वेतन पर महंगाई भत्ते में 0.01% परिवर्तन

(सी) महंगाई भत्ते की दर में परिवर्तन तिमाही आधार पर 1 मई, 1 अगस्त, 1 नवंबर और 1 फरवरी को निम्नलिखित के आधार पर जारी किया जाएगा, यथा:-

महंगाई भत्ता जारी करने की तिथि	माह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अंकों का तिमाही औसत	माह हेतु लागू
1 मई	जनवरी, फरवरी एवं मार्च	मई, जून एवं जुलाई
1 अगस्त	अप्रैल, मई एवं जून	अगस्त, सितंबर एवं अक्टूबर
1 नवंबर	जुलाई, अगस्त एवं सितंबर	नवंबर, दिसंबर एवं जनवरी
1 फरवरी	अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर	फरवरी, मार्च एवं अप्रैल;

(डी) महंगाई भत्ते की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ;

(ई) तिमाही औसत निकालते समय, केवल पहले दो दशमलवों पर ही विचार किया जाएगा ।

(बी) उप नियम (8) के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“(बी) विनियम 5 के उप-विनियम (2) में स्पष्टीकरण के खंड (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच) और (आई) में यथानिर्दिष्ट व्यावसायिक अर्हता भत्ता या व्यावसायिक अर्हता वेतन , महंगाई भत्ते के लिए रैंक किया जाएगा ।”

6. उक्त विनियमों के विनियम 22 में , उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

1 नवंबर, 2022 को एवं से,—

(ए) जहां अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, वहां वेतनमान के प्रथम स्तर में मूल वेतन के 0.35 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, उससे वसूल किया जाएगा;

(बी) जहां अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की गई है, वहां अधिकारी निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होगा , यथा :-

तालिका

क्र.सं.	तैनाती स्थल	मकान किराया भत्ता
(1)	(2)	(3)
(2)	में प्रमुख "ए" श्रेणी के शहर तथा ग्रुप ए परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 10.0%
(3)	क्षेत्र I के अन्य स्थान तथा ग्रुप बी में परियोजना क्षेत्र केंद्र तथा गोवा राज्य	वेतन का 9.0%
(4)	अन्य स्थान	वेतन का 8.0%:

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता उसके द्वारा आवासीय सुविधा के लिए भुगतान किया गया वास्तविक किराया होगा जो उपर्युक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150 प्रतिशत के साथ उसके पदस्थ वेतनमान के प्रथम स्तर में देय 0.35 प्रतिशत से अतिरिक्त होगा।

नोट :- अधिकारियों के उनके स्वामित्व आवास की लागत से जुड़े मकान किराया भत्ते के दावे को भी पूर्ववत मकान किराया भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा।

7. उक्त विनियमों के विनियम 23 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"23.(1)1 नवंबर, 2022 को एवं से, यदि कोई अधिकारी नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित स्थान पर सेवा कर रहा है, तो उस स्थान के प्रति कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट दर पर उसे नगर प्रतिपूरक भत्ता(सीसीए) देय होगा:—

तालिका

क्र.सं.	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	क्षेत्र 1 तथा उससे ऊपर तथा गोवा राज्य में स्थित स्थान	₹ 2300/- प्रति माह
2.	पांच लाख तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान तथा राज्यों की राजधानियाँ तथा चंडीगढ़, पुडुचेरी तथा पोर्ट ब्लेयर	₹ 1900/- प्रति माह.

(2) 1 नवंबर, 2022 को एवं से, विशेष क्षेत्र भत्ते की दरें इन विनियमों की अनुसूची में यथानिर्दिष्ट अनुसार होंगी:

बशर्ते कि जहां अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट किसी भी स्थान पर उप-विनियम (10) के अंतर्गत प्रदान किए गए पर्वतीय और ईंधन भत्ते भी देय हैं, तो अधिकारी दोनों भत्तों में से केवल उच्चतर भत्ते को प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, दोनों को नहीं।

बशर्ते आगे कि दोनों भत्तों में से ऐसा उच्चतर भत्ता, अधिकारी द्वारा 31 दिसम्बर, 1989 को लिए गए विशेष भत्ते और पर्वतीय एवं ईंधन भत्ते के योग से कम है तो ऐसे अंतर को तब तक व्यक्तिगत भत्ते के रूप में संरक्षित किया जाएगा जब तक अधिकारी उस स्थान पर रहता है।

(3) 1 नवंबर, 2017 को एवं से, यदि कोई अधिकारी समूह ए या समूह बी के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट परियोजना क्षेत्र में सेवारत है, तो वह परियोजना क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ते के लिए पात्र होगा, जो समूह 'ए' या समूह 'बी' के रूप में क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार क्रमशः ₹ 600/- प्रति माह या ₹ 525/- प्रति माह की दर से होगा

(4) 1 अप्रैल, 2024 को एवं से, यदि किसी अधिकारी को शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और यदि उसके एक या एक से अधिक बच्चे पूर्व स्थान पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वह शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक अधिकतम दो बच्चों के लिए उसके द्वारा दूसरे स्थान पर रिपोर्ट किए जाने की तिथि से प्रति माह ₹ 2500/-, प्रति बच्चा की दर से मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण के लिए भत्ते के लिए पात्र होगा।

बशर्ते कि यदि सभी बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर पढ़ना बंद कर देते हैं तो ऐसा भत्ता बंद हो जाएगा।

(5) 1 अप्रैल, 2024 को एवं से, यदि किसी अधिकारी को बैंक के बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो वह उस पद से जुड़ी परिलब्धियां प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, जिस पर उसे प्रतिनियुक्त किया गया है, या वह अपने वेतन के अतिरिक्त, अधिकतम प्रति माह ₹ 7500/- के अधीन वेतन के 7.75 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त कर सकता है, तथा ऐसे अन्य भत्ते जो उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने पर प्राप्त होते :

बशर्ते कि जहां ऐसे अधिकारी को किसी ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है जो उसी स्थान पर पदस्थ है या प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जो बैंक के स्वामित्व वाले नहीं हैं जहां वह अपनी प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले तैनात था या प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बैंक के स्वामित्व वाले नहीं है, तो उसे अधिकतम प्रति माह ₹ 3750/- के अधीन अपने वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त होगा:

बशर्ते आगे कि जहां किसी अधिकारी को उसी नगरपालिका सीमा या शहरी समुदाय के भीतर किसी अन्य कार्यालय या शाखा में प्रतिनियुक्त किया जाता है, मेट्रो या प्रमुख ए श्रेणी के शहरों में जहां ऐसी प्रतिनियुक्ति की दूरी मूल शाखा या कार्यालय से बीस किलोमीटर या उससे अधिक है, वह विनियम 41 के उप-विनियम (4) में यथा प्रदत्त विराम भत्ते के लिए पात्र होगा।

(6) 1 अप्रैल, 2024 से, यदि किसी अधिकारी को उच्चतर वेतनमान के किसी पद पर एक समय में कम से कम चार दिन या एक कैलेंडर माह में कुल मिलाकर चार दिन तक स्थानापन्न कार्य करना अपेक्षित है, तो उसे स्थानापन्न अवधि के लिए यथानुपात उसके मूल वेतन का 15 प्रतिशत, के बराबर स्थानापन्न भत्ता

प्राप्त होगा और स्थानापन्न भत्ते की गणना केवल भविष्य निधि और पेंशन के प्रयोजनों के लिए वेतन के रूप में की जाएगी :

बशर्ते कि, जहां कोई अधिकारी विनियम 6 के अंतर्गत पदों के वर्गीकरण की समीक्षा के परिणामस्वरूप उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न के रूप में कार्य करने के लिए आता है, तो वह वर्गीकरण की समीक्षा प्रभावी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।

- (7) 1 अप्रैल, 2024 को एवं से, कोई अधिकारी प्रत्येक लेखाबन्दी के लिए प्रति तिमाही ₹ 1500/- की लेखाबन्दी के भत्ते के लिए पात्र होगा।
- (8) 1 नवंबर, 2017 को एवं से, यदि एक दिन के दौरान कार्य के घंटे दो घंटे के न्यूनतम अंतराल के साथ विभाजित किए जाते हैं, तो एक अधिकारी ₹ 300 प्रति माह की दर से स्प्लिट ड्यूटी भत्ते के लिए पात्र होगा।
- (9) यदि किसी अधिकारी का अवकाश के दिन वॉल्ट या लॉकर के अभिसंरक्षक के रूप में कार्य करना अपेक्षित है, तो वह अपनी पात्रानुसार महंगाई भत्ते के लिए पात्र होगा।

- (10) "1 नवंबर 2022 को एवं से, कोई भी अधिकारी नीचे दी गई तालिका में यथानिर्दिष्ट पर्वतीय तथा ईंधन भत्ते के लिए पात्र होगा, यथा :-

तालिका

क्र.सं.	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	1000 मीटर या उससे अधिक परंतु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान और मर्कारा टाउन	वेतन का 2 प्रतिशत, अधिकतम सीमा प्रति माह ₹ 1450/-
2.	1500 मीटर या उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 2.5 प्रतिशत, अधिकतम सीमा प्रति माह ₹ 1900/-
3.	3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 5 प्रतिशत, अधिकतम सीमा प्रति माह ₹3750/-.

- (11) 1 नवंबर, 2022 को एवं से, अधिकारी महंगाई भत्ते के साथ प्रति माह ₹ 850/- के शिक्षण भत्ते के लिए पात्र होगा।

नोट: शिक्षण भत्ते के साथ उस पर लागू महंगाई भत्ते के गणना को अधिवार्षिता लाभों, अर्थात् परिभाषित अंशदान पेंशन योजना(नई पेंशन योजना), भविष्य निधि और उपादान सहित पेंशन के लिए नहीं जाएगी।

(12) 1 नवंबर, 2022 को एवं से, ऐसे अधिकारी जो नगर प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में तैनात हैं, वे ₹1200/- प्रतिमाह के नियत स्थान भत्ते के लिए पात्र होंगे। जिसकी गणना महंगाई भत्ते, अधिवर्षिता लाभ अर्थात् परिभाषित अंशदान योजना(नई पेंशन योजना), भविष्य निधि तथा उपादान सहित पेंशन के भुगतान के लिए नहीं की जाएगी।

(13) (ए) वित्तीय वर्ष 2023-24 से निम्नलिखित चयनित मानदंडों में से बैंक की प्राथमिकताओं के अनुसार बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत मैट्रिक्स के आधार पर, सभी अधिकारी कर्मचारियों को उनकी, कार्य-प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि (कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन) देय होगी:

(i) चालू खाता बचत खाता (ii) गैर-निष्पादित आस्तियां (iii) विशेष उल्लिखित खाते (iv) गैर-व्याज आय (v) कुल कारोबार (vi) लाभप्रदता (vii) आस्तियों पर प्रतिफल या इक्विटी पर प्रतिफल (viii) सरकारी योजनाएं।

(बी) कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) राशि 0-15 (अधिकतम) वेतन दिवसों (मूल वेतन + महंगाई भत्ता, में देय होगी, जो खंड (क) में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत मैट्रिक्स पर निर्भर करेगी।

8. उक्त विनियमों के विनियम 24 में,

(ए) उप-विनियम (1), के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(1) 1 नवंबर, 2022 को एवं से, कोई भी अधिकारी स्वयं तथा परिवार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, जिसके पास स्व-प्रमाणन के आधार पर ऐसा व्यय करने का प्रमाण हो, जो नीचे दी गई तालिका में यथानिर्दिष्ट दावा की गई राशियों के लिए लेखा विवरण द्वारा समर्थित हो, यथा:-

तालिका

क्र.सं.	श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन ग्रेड	₹ 13000/- प्रति वर्ष या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो
2.	वरिष्ठ प्रबंधन तथा शीर्ष कार्यपालक ग्रेड	₹ 15400/- प्रति वर्ष या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो।

नोट 1 : किसी अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता को संचित करने की अनुमति दी जा सकेगी, जो किसी भी समय यह राशि उपर्युक्त प्रदत्त अधिकतम राशि से तीन गुना अधिक न हो।

नोट 2.: कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो माह अर्थात् नवंबर, 2022 तथा दिसंबर, 2022 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी

(बी) उप-विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम सम्मिलित किए जाएंगे, यथा:-

“(4) सभी अधिकारी कर्मचारी नेत्र जांच के लिए प्रति वर्ष ₹ 500/- की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र होंगे।

9. उक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

“(2) उप-विनियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, 1 नवंबर, 2022 को एवं से, बैंक किसी अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए अधिकारी को पदस्थ वेतनमान के प्रथम स्तर में मूल वेतन के 0.35 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा:

बशर्ते कि जहां अधिकारी को ऐसे आवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया गया हो, वहां पदस्थ वेतनमान के प्रथम स्तर में मूल वेतन के 0.075 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि बैंक द्वारा उससे वसूल की जाएगी:

बशर्ते आगे कि जहां ऐसी आवासीय सुविधा बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, वहां बिजली, पानी, गैस तथा सुरक्षा संबंधी शुल्क अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।

10. उक्त विनियमों के विनियम 31 में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किया जाएगा, यथा:-

“बशर्ते कि जहां स्वीकृतिदाता प्राधिकारी, अधिकारी का अवकाश अस्वीकृत करता है या उसे स्थगित करता है, वहां वह उसके कारणों को लिखित रूप में अभिलेखित करेगा।”

11. उक्त विनियमों के विनियम 32 में, उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम सम्मिलित किया जाएगा, यथा:-

“(3) 1 अप्रैल, 2024 को एवं से , कोई अधिकारी कर्मचारी एक वर्ष में चार अवसरों पर आधे दिन के लिए दो दिन के आकस्मिक अवकाश लेने के लिए पात्र होगा , जिसमें से दो अवसर प्रातः और दो अवसर दोपहर के होंगे:

बशर्ते कि इस श्रेणी के अंतर्गत आकस्मिक अवकाश चौबीस घंटे पूर्व आवेदन करने के पश्चात लिया जाएगा:

बशर्ते, आगे कि आकस्मिक अवकाश के शेष को अप्रयुक्त आकस्मिक अवकाश खाते में ले जाते समय , शेष में कोई अंश, यदि कोई हो, को उपेक्षित कर दिया जाएगा । ”

12. उक्त विनियमों के विनियम 33 में:-

(ए) उप-विनियम (4) और (5) के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा :-

“(4) 1 जून, 2015 को एवं से, विशेषाधिकार अवकाश अधिकतम दो सौ सत्तर दिनों तक संचित किया जा सकेगा, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां अवकाश के लिए आवेदन किया गया हो तथा उसे अस्वीकार कर दिया गया हो:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 को एवं से विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण अधिकतम दो सौ पचपन दिनों तक सीमित होगा :

बशर्ते आगे कि कोई अधिकारी अपनी रुचि के किसी भी त्यौहार के समय प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए पांच दिन की दर से विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए भी पात्र होगा और कोई अधिकारी जो पहले ही पचपन वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुका है, वह अपनी सेवानिवृत्ति तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए सात दिनों की दर से विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए पात्र होगा ।

(5) विशेषाधिकार अवकाश का लाभ उठाने वाले इच्छुक अधिकारी को सामान्यतः अवकाश किराया रियायत के प्रयोजन को छोड़कर, ऐसे अवकाश का लाभ उठाने के अपने इरादे की कम से कम दस दिन पहले सूचना देनी होगी:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 को एवं से पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार अवकाश का लाभ लेने के लिए दस दिनों की ऐसी कोई अग्रिम सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

(बी) उप-विनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम सम्मिलित किया जाएगा, यथा:-

“(7) 1 अप्रैल, 2024 को एवं से विशेषाधिकार अवकाश की गणना के प्रयोजनों के लिए, आकस्मिक अवकाश और अनिवार्य अवकाश को छोड़कर लिए गए सभी प्रकार के अवकाश को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।।

13. उक्त विनियमों के विनियम 34 में,—

(ए) उप-विनियम (1) में , निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 को एवं से , कोई भी अधिकारी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक माह की दर से अस्वस्थता अवकाश के लिए पात्र होगा :

बशर्ते कि अस्वस्थता अवकाश की कुल संख्या (विनियम 35 में उल्लिखित अतिरिक्त अस्वस्थता अवकाश सहित) अधिकारी की सम्पूर्ण सेवा में सात सौ बीस दिन से अधिक नहीं होगी।”

(बी) उप-विनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

“(6) 1 अप्रैल, 2024 को एवं से, एकल पुरुष अभिभावक कर्मचारी अपने आठ वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की अस्वस्थता के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अस्वस्थता अवकाश का लाभ उठा सकता है।

(7) 1 अप्रैल, 2024 को एवं से महिला कर्मचारी बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए प्रति माह एक दिन का अस्वस्थता अवकाश ले सकती हैं।

(8) 1 अप्रैल, 2024 को एवं से, अधिकारी कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके अपने पंद्रह वर्ष या उससे कम आयु के विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की अस्वस्थता के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दस दिनों की अवधि के लिए अस्वस्थता अवकाश का लाभ उठा सकते हैं।

(9) 1 अप्रैल, 2024 को एवं से, अट्ठावन वर्ष या उससे अधिक आयु के अधिकारी कर्मचारी, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम तीस दिनों की अवधि के लिए तैनाती स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य केंद्र पर अपने पति/पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने पर अस्वस्थता अवकाश का लाभ उठा सकते हैं।

14. उक्त विनियमों के विनियम 36 के, उप-विनियम (1) में, -

(ए) खंड (ए) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ए) महिला कर्मचारी किसी एक अवसर पर अधिकतम छः माह की अवधि के लिए तथा अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम बारह माह के लिए मूल वेतन पर मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होगी:

बशर्ते कि जुड़वा बच्चों के जन्म के मामले में मातृत्व अवकाश की अवधि आठ माह होगी:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 को एवं से एक ही प्रसव में दो से अधिक बच्चों के जन्म की स्थिति में मातृत्व अवकाश की अवधि बारह माह होगी।

बशर्ते कि मातृत्व अवकाश के साथ आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश को जोड़ा जा सकेगा ”

(बी) खंड (डी) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(1) (डी) एक महिला कर्मचारी एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए सेवा के दौरान एक बार अधिकतम नौ महीने की अवधि के लिए अवकाश ले सकती है, जो निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगा, अर्थातः -

- (i) केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए अवकाश दिया जाएगा;
- (ii) बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए तथा ऐसी अवकाश स्वीकृति के लिए कर्मचारीको बैंक के समक्ष गोद लेने का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा ।
- (iii) यह अवकाश उन मामलों में बायोलोजिकल माँ को भी उपलब्ध होगा जहां बच्चे का जन्म सरोगेसी के माध्यम से हुआ हो ;
- (iv) अवकाश का लाभ सम्पूर्ण सेवा काल के दौरान बारह महीने की समग्र पात्रता के भीतर लिया जाएगा ”

(सी) खंड (ई) के बाद, निम्नलिखित खंड सम्मिलित किए जाएंगे, यथा:-

(एफ) 1 अप्रैल, 2024 को एवं से, बारह महीने की समग्र सीमा के भीतर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन इन विट्रो फर्टिलिटी (आईवीएफ) उपचार के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है।

(जी) 1 अप्रैल, 2024 को एवं से, महिला कर्मचारी द्वारा शिशु के मृत जन्म या जन्म के अट्ठाईस दिनों के भीतर शिशु की मृत्यु की स्थिति में साठ दिनों तक विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है।

15. उक्त विनियम के विनियम 37ए के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“37ए. विशेष आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश- (1) 1 नवंबर, 2020 से प्रभावी, कोई अधिकारी कर्मचारी उन अवसरों पर विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा जब वह शाखा जहां अधिकारी कार्यरत है अथवा वह स्थान जहां वह रह रहा है, कर्फ्यू, दंगों, निषेधाज्ञा, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ आदि और इसी तरह से प्रभावित होता है।

(2) 1 नवंबर, 2020 से प्रभावी, शारीरिक या अस्थि विकलांग अधिकारी चार दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होंगे।

(3) 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी अखिल भारतीय अधिकारी संघों या एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारी को एक कैलेंडर वर्ष में पच्चीस दिन का विशेष अवकाश प्रदान किया जाएगा।

(4) 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी, विभागीय जांच में बचाव प्रतिनिधि अधिकारी, किसी अधिकारी कर्मचारी का बचाव प्रस्तुतीकरण तैयार करने के उद्देश्य से एक दिन का विशेष अवकाश ले सकते हैं :

बशर्ते कि ऐसी विशेष छुट्टी एक वर्ष में अधिकतम दस अवसरों के लिए ली जा सकती है।

(5) किसी अधिकारी को विशेष आकस्मिक अवकाश या कोई भी विशेष अवकाश प्रदान किया जा सकता है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा।

16. उक्त विनियमों के विनियम 37 ए के पश्चात् निम्नलिखित विनियम सम्मिलित किया जाएगा, यथा:

“37 बी. शोक अवकाश.- किसी अधिकारी /कर्मचारी को परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी, बच्चों, माता-पिता तथा सास-ससुर) की मृत्यु पर समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित दिनों के लिए शोक अवकाश प्रदान किया जाएगा;

बशर्ते आगे कि बीच में पड़ने वाले अवकाश शोक छुट्टियों का हिस्सा होंगे:

बशर्ते यह भी कि उक्त अवकाश का उपयोग मृत्यु के अधिकतम पंद्रह दिनों के भीतर किया जाना चाहिए:

बशर्ते कि उक्त अवकाश को विशेषाधिकार अवकाश की गणना के प्रयोजनार्थ "सक्रिय सेवा" नहीं माना जाएगा।

17. उक्त विनियमों के विनियम 41 में, -

(ए) उप - विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

“(1) 1 अप्रैल, 2024 को एवं से, जहां कहीं भी किसी अधिकारी को ड्यूटी पर यात्रा करना आवश्यक होगा, वहां निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, यथा : -

(ए) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड का कोई अधिकारी राजधानी या शताब्दी या तेजस या वंदे भारत या अमृत भारत आदि जैसी प्रीमियम ट्रेनों सहित किसी भी ट्रेन में एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का पात्र होगा (लक्जरी ट्रेनों को छोड़कर):

बशर्ते कि ऐसे अधिकारी, कारोबार अथवा लोकहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दिए जाने पर, हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है;

(बी) मध्य प्रबंधन ग्रेड का कोई अधिकारी खंड (क) में उल्लिखित प्रीमियम ट्रेनों सहित किसी भी ट्रेन में एसी प्रथम श्रेणी से यात्रा करने का पात्र होगा :

बशर्ते कि यदि यात्रा की जाने वाली दूरी 500 किलोमीटर से अधिक हो तो वह हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है:

बशर्ते आगे कि वह कम दूरी के लिए भी हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारोबार अथवा लोकहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी अनुमति दी गई हो;

(सी) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक ग्रेड का कोई अधिकारी प्रीमियम ट्रेनों सहित किसी भी ट्रेन (जैसा कि खंड (क) में उल्लिखित है) द्वारा एसी प्रथम श्रेणी में या हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) द्वारा एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का पात्र है;

(डी) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक ग्रेड का कोई अधिकारी हवाई या रेल मार्ग से न जुड़े स्थानों के मध्य कार से यात्रा कर सकता है, बशर्ते कि दूरी पाँच सौ किलोमीटर से अधिक न हो।

बशर्ते कि जब दो स्थानों के बीच की दूरी का अधिकांशतः भाग हवाई या रेल मार्ग द्वारा तय किया जा सकता हो, तो केवल शेष दूरी सामान्यतः कार द्वारा तय की जानी चाहिए;

(ई) किसी अन्य अधिकारी को कारोबार की आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने स्वयं के वाहन या टैक्सी अथवा बैंक के वाहन से यात्रा करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है;

(एफ़) किसी भी ग्रेड या स्केल का अधिकारी सड़क या हवाई या रेल से न जुड़े स्थानों के बीच डीलक्स केबिन श्रेणी में जल परिवहन द्वारा यात्रा करने के लिए पात्र होगा;

(जी) अधिकारी प्रीमियम ट्रेनों (लक्जरी ट्रेनों को छोड़कर) के किराए के लिए पात्र होगा।

नोट 1: रेल किराये पर लगाया जाने वाला वस्तु एवं सेवा कर शुल्क पात्रता से अतिरिक्त होगा।

नोट 2: प्रचलित गतिशील किराया प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, बुकिंग की तिथि पर ली गई रेल टिकट की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी”:

(बी) उप-विनियम (4) में, खंड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“ (ए) **विराम भत्ता.**- 1 अप्रैल, 2024 को एवं से, तालिका के कॉलम (2) में दिए गए ग्रेड या स्केल में कोई अधिकारी कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी दरों पर 'दैनिक' विराम भत्ते का हकदार होगा, अर्थात्:-

तालिका

क्र.सं.	अधिकारियों के ग्रेड या वेतनमान	विराम भत्ता			
		महानगर ₹	प्रमुख 'ए' श्रेणी शहर ₹	क्षेत्र I ₹	अन्य स्थान ₹
(1)	(2)	(3)			
1.	वेतनमान VI एवं उससे ऊपर के अधिकारी	4050	2925	2475	2150
2.	वेतनमान IV एवं V के अधिकारी	3375	2925	2475	2150
3.	वेतनमान I, II एवं III के अधिकारी	2925	2475	2150	1800 :

बशर्ते कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम किन्तु चार घंटे से अधिक हो, वहां उपर्युक्त

दरों की आधी दर पर विराम भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण .-- विराम भत्ते की गणना करने के प्रयोजन के लिए "दैनिक" का अर्थ चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि या उसका कोई पश्चात्तवर्ती भाग होगा, जिसकी गणना हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय से या अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से लेकर आगमन के वास्तविक समय तक की जाएगी तथा जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, वहां "दैनिक" का अर्थ आठ घंटे से कम की अवधि नहीं होगी।

18. उक्त विनियमों के विनियम 42 में,—

(ए) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

“(3) 1 अप्रैल, 2024 को एवं से, स्थानांतरण पर आने वाला अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा आदि से जुड़े खर्चों के लिए एकमुश्त राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात: -

तालिका		
क्र. सं.	ग्रेड या वेतनमान	राशि
(1)	(2)	(3)
1.	वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यपालक (वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी)	₹50000/-
2.	कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन (वेतनमान III तक के अधिकारी)	₹40000/-

(बी) उप-विनियम (4) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:

““बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 को एवं से, जहां बैंक द्वारा किसी अधिकारी को नए तैनाती स्थल पर कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है तथा जहां ऐसे अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया में अपने नियंत्रण से परे कारणों से अतिरिक्त व्यय करना पड़ा है, सक्षम प्राधिकारी, नए स्थान पर ऐसे अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, गुण-दोष के आधार पर पंद्रह दिनों की अवधि के लिए या जब तक क्वार्टर उसे उपलब्ध नहीं करा दिए जाते हैं, जो भी पहले हो, आवास और भोजन प्रभार या विराम भत्ता देने पर विचार कर सकता है। ”

19. उक्त विनियमों के विनियम 44 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

“44 (1) छुट्टी यात्रा रियायत – (1)चार वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक के दौरान, अधिकारी दो वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार अपने निवास स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि, वह दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने निवास स्थान तक और दो वर्ष के दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान तक सबसे छोटे मार्ग से यात्रा कर सकता है:

- (2) 1 अप्रैल, 2024 को एवं से, वैकल्पिक रूप से, कोई अधिकारी चार वर्ष के ब्लॉक या दो वर्ष के ब्लॉक के दौरान किसी भी समय विकल्प का प्रयोग करके, जैसा भी मामला हो, अपनी छुट्टी यात्रा रियायत (निवास स्थान की यात्रा के अलावा) का नकदीकरण कर सकता है, जिसके अंतर्गत वह ट्रेन द्वारा यात्रा की उस श्रेणी के लिए पात्र किराए के समान राशि प्राप्त करने का पात्र होगा, जिसके लिए वह कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान I, मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान II और मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान III के अधिकारियों के लिए 5,500 किलोमीटर (एक तरफ से) की दूरी तक और वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए 6,500 किलोमीटर (एक तरफ) की दूरी का पात्र है:

बशर्ते कि कोई अधिकारी जो अपनी छुट्टी यात्रा रियायत के नकदीकरण के विकल्प का चयन करता है, वह उस ब्लॉक के दौरान, जिसमें ऐसी नकदीकरण सुविधा ली जाती है, केवल एक बार ही अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए दावा प्रस्तुत कर सकेगा तथा छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा को भुनाने समय, छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा का लाभ उठाते समय, विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

- (3) जिस माध्यम और वर्ग से कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठा सकता है, वह वही होगा जिसके लिए अधिकारी सामान्यतः स्थानांतरण पर यात्रा करने का पात्र होता है और अन्य निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठा सकता है, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी।:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान I का अधिकारी, छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाते हुए, सबसे कम किराया वाली इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने का पात्र होगा, जिस स्थिति में प्रतिपूर्ति वास्तविक किराया या यात्रा की गई दूरी के लिए ट्रेन द्वारा ऐसी प्रथम श्रेणी के किराए के लिए लागू किराया, जो भी कम हो, होगी तथा यही नियम तब लागू होंगे जब मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान II और मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान III का कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाता है, जहां दूरी 500 किलोमीटर से कम है।

- (4) प्रत्येक चार वर्ष में एक बार, जब कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाता है, तो उसे एक बार में तीस दिन तक विशेषाधिकार अवकाश को समर्पित करने और नकदीकरण/भुनाने की अनुमति दी जा सकती है अथवा दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने गृह नगर और दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी स्थान की यात्रा करते समय, प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम पंद्रह दिन या एक ब्लॉक में तीस दिन के विशेषाधिकार अवकाश के भुनाने की अनुमति दी जा सकती है और अवकाश भुनाने के प्रयोजन के लिए उस माह के

लिए देय सभी परिलब्धियां, जिसके दौरान छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाया गया है, स्वीकार्य होंगी :

बशर्ते कि किसी अधिकारी को, उसके विकल्प पर, प्रधानमंत्री राहत कोष में दान के लिए एक दिन के अतिरिक्त विशेषाधिकार अवकाश को भुनाने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वह इस आशय का एक पत्र बैंक को दे तथा बैंक को कोष में राशि भेजने के लिए प्राधिकृत करे।

- (5) जहां पति और पत्नी दोनों एक ही बैंक में कार्यरत हैं, वहां अवकाश यात्रा रियायत का लाभ स्वतंत्र रूप से उठाया जा सकता है।
- (6) पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत कार्मिकों के लिए अवकाश यात्रा रियायत गुवाहाटी से शुरू होगी तथा उनके कार्यस्थल से गुवाहाटी तक का पात्र रेल किराया अतिरिक्त रूप से भुगतान किया जाएगा।
- (7) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से चेन्नई या कोलकाता, लक्षद्वीप से कोच्चि, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर में दूर-दराज के क्षेत्रों की शाखाओं या किसी अन्य क्षेत्र जो सीधे ट्रेन से नहीं जुड़े हैं, के लिए पात्र किराया इन क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों के लिए निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन तक सामान्य पात्रता के अतिरिक्त छुट्टी यात्रा रियायत के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (8) यात्रा के दौरान बेंचमार्क अक्षमता वाले अधिकारी के साथ अनुरक्षक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवकाश यात्रा रियायत सुविधा दी जाएगी, यथा :
 - (ए) प्रत्येक अवसर पर सक्षम प्राधिकारी का अग्रिम अनुमोदन प्राप्त किया जाए है ;
 - (बी) अधिकारी की शारीरिक अक्षमता की प्रकृति ऐसी हो कि यात्रा के लिए अनुरक्षक की आवश्यकता हो और संदेह की स्थिति में विभागाध्यक्ष/नियंत्रक का निर्णय अंतिम होगा;
 - (सी) ऐसी बेंचमार्क अक्षमता वाले अधिकारी के साथ कोई वयस्क पारिवारिक सदस्य आश्रित के रूप में न हो;
 - (डी) ऐसी बेंचमार्क अक्षमता वाले अधिकारी तथा अनुरक्षक को रेल या बस किराये में रियायत, यदि कोई हो, का लाभ मिलेगा, जो ऐसे मामलों में रेलवे या राज्य सड़क मार्ग प्राधिकारियों द्वारा दी जा सकती है; तथा
 - (ई) कोई अन्य व्यक्ति जो आश्रित के रूप में अवकाश यात्रा रियायत का पात्र है, यदि वह ऐसे बेंचमार्क अक्षमता वाले अधिकारी के साथ यात्रा पर नहीं जाता है।
- (9) जहां किसी अधिकारी ने अवकाश यात्रा रियायत अथवा अग्रिम अवकाश के लिए आवेदन किया है अथवा तथा टिकट भी बुक कर लिया है और प्रबंधन द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत को अस्वीकार या स्थगित कर दिया जाता है, तो रद्दीकरण प्रभारों की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी।

- (10) जहां किसी अधिकारी ने निर्धारित समय के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत अथवा अवकाश के लिए आवेदन किया है तथा उसे स्वीकृति प्राप्त हो गई है तथा जब रेल टिकटों की अग्रिम बुकिंग संभव नहीं है, तो तत्काल या प्रीमियम तत्काल के अन्तर्गत खरीदे गए टिकटों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

20. उक्त विनियमों की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा :-

"अनुसूची

(विनियम 23 का उप-विनियम (2) देखें)

1 नवंबर, 2022 को एवं से, कोई भी अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए तब तक पात्र होंगे जब तक कि उसे नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार पूरी तरह या आंशिक रूप से हटाया नहीं जाता या संशोधित नहीं कर दिया जाता है, अर्थात:-

तालिका

विशेष क्षेत्र भत्ता

क्र. सं.	स्थान	भत्ते (₹ में)	भत्ते (₹ में)
		वेतन ₹ 48,481/- से कम	वेतन ₹ 48,481/- से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मिजोरम		
	(क) चिम्पटुइपुई जिला तथा 25 किलोमीटर से आगे के क्षेत्र लुंगलेई जिले के लुंगलेई कस्बे से।	4100	5300
	(ख) लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण लुंगलेई जिला।	4100	5300
	(ग) संपूर्ण आइजोल जिला	2700	3400
2.	नागालैंड	4100	5300
3.	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह		
	(ए) उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार तथा नारकोडम द्वीप समूह	4100	5300
	(ख) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	4100	5300
4.	सिक्किम	4100	5300
5.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	4100	5300
6.	असम	1000	1200
7.	मेघालय	1000	1200
8.	त्रिपुरा		
	(क) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र	4100	5300
	(ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण त्रिपुरा में	2700	3400
9.	मणिपुर	2700	3400
10.	अरुणाचल प्रदेश		
	(क) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र	4100	5300
	(ख) संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश में, दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर।	4100	5300
11.क	जम्मू तथा कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश		
	(1) कठुआ जिला : नियाबत बानी, लोही, मल्हार तथा मछोड़ी	4100	5300
	(2) उधमपुर जिला :		

	(ए) दुदु बसंतगढ़ , लैंडर भमाग इलाका, ठाकराकोट और नागोटे	4100	5300
	नीचे (ग) में शामिल क्षेत्रों के अलावा माहौर तहसील के सभी क्षेत्र	4100	5300
	(सी) कंबन साइड से गोयल तक के क्षेत्र और अरनास तक के क्षेत्र तहसील मोहरे में केसी पक्ष	4100	5300
	(3) डोडा जिला : कश्मीर तहसील में पैडर और नियाबत नौगाम के इलाका	4100	5300
	(4) बारामूला जिला :		
	(ए) संपूर्ण गुरेज़- निराबत , टंगडार सब-डिवीजन तथा केरन इलाका	4100	5300
	(बी) मैचिल	4100	5300
	(5) पुंछ और राजौरी जिले : पुंछ तथा राजौरी जिले के क्षेत्र, पुंछ और राजौरी कस्बों और सुंदरबनी तथा दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर	2700	3400
	(6) वे क्षेत्र जो उपर्युक्त (1) से (5) में सम्मिलित नहीं हैं, किन्तु जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर हैं या ऐसे स्थानों पर हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कार्मिकों के लिए सीमा भत्ते के लिए अर्हक घोषित किया जा सकता है।	2700	3400
ख	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाखः लेह जिला : नोयामा और नोब्रे जांस्कर जिले के अन्य सभी स्थान	4100	5300
12.	हिमाचल प्रदेश		
	(1) चंबा जिला		
	(ए) पांगी तहसील, भरमौर तहसील में निम्नलिखित पंचायतें और गांव : पंचायतें: बड़गांव , बाजोल , देवल कुगती, नयागाम और टुंडा गाँव: ग्राम पंचायत जगत के घाटू , ग्राम पंचायत चौहटा के कनारसी	4100	5300
	(बी) भरमौर तहसील, उपरोक्त (क) में शामिल पंचायतों और गांवों को छोड़कर	4100	5300
	(सी) भारतीयत तहसील में झंडरू पंचायत , चुराह तहसील, डलहौजी शहर (बनीखेत उचित सहित)	2700	3400
	(2) किन्नौर जिला		
	(ए) असरंग , छितकुल तथा हांगो कुनो या चारंग पंचायतें, 15/20 पूह उप-मंडल के छोटा खंबा, नाथपा और रूपी ग्राम पंचायतों वाला क्षेत्र , ऊपर निर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर	4100	5300
	उपरोक्त (क) में शामिल क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण जिला	4100	5300
	(3) कुल्लू जिला		
	निरमंड तहसील का 15/20 क्षेत्र , जिसमें खरगा , कुशवार और सरगा ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं	4100	5300
	(बी) बाहरी सराज (निरमंड तहसील में जकात-खाना और बुरो के गांवों को छोड़कर) तथा संपूर्ण जिला बाहरी सराज क्षेत्र और पंद्राबीस के परगना को छोड़कर, परंतु तहसील निरमंड के जगत-खाना और बुराओ गांवों सहित)	2700	3400
	(4) लाहौल और स्पीति जिला : लाहौल तथा स्पीति जिला	4100	5300
	(5) शिमला जिला		

(ए) रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपारा और चंडी-ब्रांडा की पंचायतें सम्मिलित हैं।	4100	5300
(बी) डोडरा -कावर तहसील, रामपुर में दरकाली की ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील और मुनीश, गोरी परगना सराहन की चाईबियाँ	4100	5300
(सी) (I) चौपाल तहसील (i) सराहन परगना के घोरी, पंजगांव, पाटसनौ, नौबीस और तीन कोटी; (ii) तकलेश की देवठी ग्राम पंचायत क्षेत्र; (iii) परगना बाराबीस; और (iv) रामपुर तहसील के परगना रामपुर के कस्बा रामपुर और गोरी नोग; (द्वितीय) शिमला शहर और उसके उपनगर (ढल्ली, जटोग, कसुम्पटी, मशोबरा, तारादेवी और टूट)	2700	3400
(6) कांगड़ा जिला:		
(ए) बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल के क्षेत्र	4100	5300
नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित परंतु धर्मशाला शहर में शामिल निम्नलिखित कार्यालय : (a) महिला आईटीआई, दारी, (b) यांत्रिक कार्यशाला, रामनगर, (c) बाल कल्याण और नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय, साकोह, (d) साकोह में सीआरएसएफ कार्यालय, (e) कांगड़ा दूध आपूर्ति योजना, डुगियार, (f) एचआरटीसी वर्कशॉप, सधेर, (g) क्षेत्रीय मलेरिया कार्यालय, दाडी, (h) वन निगम कार्यालय, शामनगर, (i) चाय फैक्ट्री, दाडी, (j) आईपीएच उप-मंडल, दाडी (k) सेटलमेंट कार्यालय, शामनगर, (l) बिनवा परियोजना, शामनगर, (II) पालमपुर शहर, जिसमें पालमपुर स्थित हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय परिसर तथा इसकी नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित परंतु पालमपुर शहर में शामिल निम्नलिखित कार्यालय सम्मिलित हैं - (क) एचपी कृषि विश्वविद्यालय परिसर, (ख) मवेशी विकास कार्यालय या जर्सी फार्म, बनुरी, (ग) रेशम उत्पादन कार्यालय या इंडो-जर्मन कृषि (घ) कार्यशाला या एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुंडला, (ङ) विद्युत उप-मंडल, लोहना, (च) डीपीओ कॉर्पोरेशन, बुंडला, (छ) इलेक्ट्रिकल एचपीएसई डिवीजन, घुग्गर	2700	3400
(7) मंडी जिला :		
जोगिंदरनगर तहसील की छुहार घाटी, थुनाग तहसील में पंचायतें : बागरा, छतरी, छोटधार, गरागुशैन, गट्ट, गैरयास, जंजैहली, जरयार, जोहार कल्हणी, कलवन, खोलानाल, लोथ, सिलिबागी, सोमाचन, थाचधार, ताची, थाना, धरमपुर ब्लॉक की निम्नलिखित पंचायतें : बिंगा, कमलाह, सकलाना, तान्यार और तारखोलाह, करसोग तहसील की पंचायतें - बालीधार, बागरा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुदी, मंज, पेखी, सैंज, सराहन और तेवन,	2700	3400

	सुन्दरनगर तहसील की पंचायतें – बोही, बटवाड़ा, धन्यारा, पौरा-कोठी, सेरी और शोजा		
	(8) सिरमौर जिला : (क) निम्नलिखित पंचायतें (i) बनी, बाखली (पच्छाद तहसील), (ii) भरोगभेनेरी (पांवटा तहसील), (iii) बिरला (नाहन तहसील), (iv) डिब्बर (पच्छाद तहसील) और (v)थाना कसोगा (नाहन तहसील) (b) थांसगिरी ट्रैक्ट	2700	3400
	(9) सोलन जिला : मंगल पंचायत।	2700	3400
	(10) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो (1) में सम्मिलित नहीं हैं (9) ऊपर	1000	1200
13 .	उत्तराखंड: चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	4100	5300
14.	पश्चिम बंगाल: दक्षिण 24 परगना जिला सुंदरबन क्षेत्र (डैम्पियर हाँज की रेखा के दक्षिण में), अर्थात्, भगतुश खली (रामपुरा), कुमिरमारी (बगना), झिंगा खली, सजनाखली, गोसाबा, अमलामाथी (बिद्या), कैनिंग, कुलतली, पियाली, नलगराहा, रायदीघ, भांची, पत्थर प्रतिमा, भागवतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, सीकरपुर, काकद्वीप, सागर, मौसिनी, कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंती, कुएमारी, कुलटोला, घुसीघटा (कुल्टी)	1000	1200 .”.

विवरणात्मक ज्ञापन

उक्त विनियम, जिन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, संयुक्त नोटों और निपटन के लिए सहमत शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार, संबंधित बैंकों द्वारा इस संबंध में दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ तथा बैंकों के शीर्ष स्तरीय अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित है। अतः, ऐसे पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सुमेश कुमार, मुख्य महाप्रबंधक
[विज्ञापन-III/4/असा./215/2026-27]

PUNJAB NATIONAL BANK

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2026.

F. No. HRDD/POL/OSR/(F).—In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Punjab National Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, except as respects things done or omitted to be done in pursuance of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, letter number 4/2/1/2022-IR, dated the 13th March, 2024, on and from the 1st November, 2022 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, hereby makes the following regulations further to amend the Punjab National Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Punjab National Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Punjab National Bank (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely: -

“(f) ‘family’, in relation to an officer employee for the purposes of medical facilities and for the purpose of leave fare concession, shall mean-

- (i) the officer employee's spouse;
- (ii) wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children);
- (iii) wholly dependent physically and mentally challenged brothers or sisters with forty per cent. or more disability;
- (iv) widowed daughters and dependent divorced or separated daughters;
- (v) sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters; and
- (vi) parents wholly dependent on the employee:

Provided that in the case of physically or mentally challenged children, irrespective of age, they shall be construed as dependents even after their marriage subject to fulfilling the income criteria for dependent.

Explanation 1.- The expression “wholly dependent family member’ shall mean such member of the family having a monthly income not exceeding Rs.18,000/- and if the monthly income of one of the parents exceeds Rs.18,000/- or the aggregate of monthly income of both the parents exceeds Rs. 18,000/-, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the Officer employee.

Explanation 2.-For the purposes of medical expenses reimbursement scheme, and Leave Fare Concession for all Officers, any two of the dependent father, mother, father-in-law, mother-in-law shall be covered. The Officer shall have the choice to substitute either of the dependents or both once in a calendar year.

Explanation 3.-This definition shall be effective from the 1st April, 2024 and for the calendar year 2024, for the purpose of medical insurance scheme or policy, the revised monthly income criteria of dependents shall be effective from the 1st November, 2024.”.

3. In regulation 4 of the said regulations.,-

(a) the *explanation* to sub-regulation (7) shall be omitted;

(b) for sub-regulations (9) and (10), the following shall be substituted, namely:-

“(9) On and from the 1st November, 2022, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

(a) Top Executive Grade

Scale VIII= Rs.253000- 9000/4- 289000

Scale VII = Rs.156500 – 4340/4 – 173860

Scale VI = Rs.140500 - 4000/4 – 156500

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.120940 – 3360/2 – 127660 – 3680/2 - 135020

Scale IV = Rs.102300 – 2980/4 – 114220– 3360/2 – 120940

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs.85920-2680/5– 99320 - 2980/2 - 105280

Scale II = Rs. 64820–2340/1 - 67160 -2680/10 - 93960

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.48480-2000/7- 62480-2340/2-67160-2680/7-85920.

Explanation.- Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31st October, 2022 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1st November, 2022 on stage-to-stage basis, that is, on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual, except where provided otherwise.

(10) Nothing in sub-regulations (1) to (9) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(11) On and from 1st day of November, 2012, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I – III - 7.75 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V - 10 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI – VII - 11 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

(12) On and from the 1st day of November, 2017, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I – III - 16.40 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V - 19 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI - VIII - 20 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Provided that an Officer in Scale-VIII will be eligible for special allowance on and from the 31st March, 2020.

(13) On and from 1st day of November, 2022, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I - 26.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale II – III - 28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale IV – V - 30.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale VI - VII -31.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale VIII -28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Note: The special allowance referred to sub-regulation (11), (12) and (13) with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including Defined Contribution Pension Scheme (National Pension Scheme), Provident Fund and Gratuity”.

4. In regulation 5 of the said regulations, -

- (a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (9) of regulation 4, on and from the 1st November, 2022, the increments shall be granted subject to the following conditions, namely: -

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (9) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) one year after reaching maximum in their respective scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment in the next higher Scale only as specified in clause (c) below, subject to their crossing the efficiency bar;
- (c) officers in Junior Management Grade Scale I, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher Scale, shall be eligible for seven stagnation increments for every two completed years of service of which the first two shall be Rs. 2680/- each and the next five shall be of Rs 2980/- each:

Provided that the officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (d) officers in the Middle Management Grade Scale II, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b), after reaching maximum of higher scale, shall be eligible for seven stagnation increments of Rs. 2980/- each for every two completed years of service:

Provided that the officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later:

- (e) officers in substantive Middle Management Grade Scale III, that is, those who are recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III shall be eligible for eight stagnation increments for every two years of completed service after reaching the maximum of scale out of which first four stagnation increments shall be of Rs. 2980/- and the next four stagnation increments shall be of Rs. 3360/- each:

Provided that the officer shall be eligible for seventh stagnation increment two years after release of sixth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later.

Provided further that the officer shall be eligible for the eighth stagnation increment four years after release of sixth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (f) officers in Senior Management Grade Scale IV shall be eligible for five stagnation increments for every two completed years of service after reaching the maximum of scale, of which first stagnation increment shall be of Rs. 3360/- and the next four stagnation increments shall be of Rs. 3680/- each:

Provided that the officer shall be eligible for the third stagnation increment two years after release of second stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the fourth stagnation increment four years after release of second stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that the officer shall be eligible for the fifth stagnation increment six years after release of second stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (g) officers in Senior Management Grade Scale V shall be eligible for four stagnation increments of Rs. 4000/- each for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that the officer shall be eligible for the second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the third stagnation increment six years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that the officer shall be eligible for the fourth stagnation increment eight years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (h) officers in Top Management Grade Scale VI shall be eligible for three stagnation increments for every two completed years of service after reaching the maximum scale of pay, out of which first two stagnation increments shall be of Rs 4000/- each and the third stagnation increment shall be of Rs 4340/-:

Provided that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment of Rs 4000/- two years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment of Rs 4000/- four years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment of Rs 4340/- six years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

- (i) officers in Top Management Grade Scale VII shall be eligible for three stagnation increments of Rs. 4340/- each for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment, two years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment, six years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Note: The increments as mentioned above in clauses (a) to (i) of this sub-regulation shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation. - Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.”;

- (b) in sub-regulation (2),-

- (i) before the *explanation*, the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided that on and from the 1st November, 2022, officers completing Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination or (Certified Associate of Indian Institute of Bankers -II) shall be eligible for two increments in their scale of pay apart from one increment for completing Junior Associate of Institute of Indian Bankers’ examination or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination:

Provided further that Officers who were in the services of the Bank as on the 1st November 2022 and have already completed Certified Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination II shall be eligible for second additional increment from 1st November, 2022 or date of passing Certified Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination II, whichever is later.

Provided also that in case where an officer, as on the 8th March 2024, has already acquired or acquire, Junior Associate of Institute of Indian Bankers’ examination / Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination I or Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination II, or after reaching maximum of the scale of pay (in case of Junior Associate of Institute of Indian Bankers’ or Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination), or after reaching the stage which is one stage less than maximum of scale of pay [in case of Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination (Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination II)], and has not earned increments, otherwise entitled on account of acquiring such qualification, when there were no increments to provide in the scale of Pay of those employees, the stagnation increment in such cases may be advanced by one year or two years as the case may be.”;

- (ii) in the *Explanation*, after clause (h) and before the Note, the following clause shall be

inserted, namely:-

“(i) on and from the 1st November, 2022, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the following table, namely:-

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers Part I	Rs.1370/- per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers or both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers II	(a) Rs.1370/- per month one year after reaching maximum of the Scale; (b) Rs.3425/- per month two years after reaching maximum of the Scale; and (c) Rs.5480/- per month three years after reaching maximum of the Scale:

Provided that an officer employee acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification, the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay.”:

Provided further that on and from the 1st day of November, 2022, no Professional Qualification allowance shall be payable to an officer employee working in Scale VIII.”;

(iii) in the Note, after clause (v), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(vi) officers who were in the services of the Bank as on the 1st November, 2022 and have already completed Junior Associate of Indian Institute of Bankers I (Certified Associate of Indian Institute of Bankers I) or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (Certified Associate of Indian Institute of Bankers II) and drawing Professional Qualification Pay -II shall be eligible for Professional Qualification Pay -III one year after the release of Professional Qualification Pay-II or from the 1st November, 2022, whichever is later.

(vii) officers who have completed Junior Associate of Indian Institute of Bankers (Certified Associate of Indian Institute of Bankers -I) or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (Certified Associate of Indian Institute of Bankers -II) and has reached the maximum in the scale of pay on or before 1st November, 2022 and has not received the 1st stagnation increment on or before 1st November 2022, shall be eligible for Professional Qualification Pay-I on and from the 1st November, 2022 and release of subsequent instalment of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of Professional Qualification Pay I under this clause.”;

(c) in sub-regulation (3),-

(i) the note after clause (g), shall be deleted;

(ii) after clause (h), the following shall be inserted, namely:-

- “(i) on and from the 1st November, 2022, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 01.11.2022 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
2680	200	2880
2980	222	3202
3360	250	3610
3680	274	3954
4000	298	4298
4340	323	4663
9000	669	9669

Note:

- (i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the Tables in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g) (h) and (i) of this sub-regulation shall be payable to those officers employees who are provided with Bank's accommodation.
- (ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the Table under clause (i) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub regulations (2),(3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9) of regulation 4 is earned;
- (iii) Only officers who are in the service of the Bank on or before the 1st November, 1993 shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay, they are placed.
- (iv) On and from the 1st November, 1999, there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in clause (c) of the *Explanation* to sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after 1st November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on 1st November, 2000.
- (v) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.
- (vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) above, one year after reaching the maximum of the scale.

5. In regulation 21 of the said regulations,-

(a) after sub-regulation (7) and before the *Explanation*, following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(8) On and from the 1st November, 2022,-

(a) Dearness Allowance shall be payable at 1 per cent. of pay per percentage point of Index;

(b) Dearness Allowance in the above manner shall be paid for every variation of rise or fall over 123.03 points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index (CPI) for Industrial Workers Base 2016=100. 0.01 per cent. change in Dearness Allowance on pay for change in every second decimal place of CPI 2016 over 123.03 points;

(c) the change in the Dearness Allowance rate shall be released on a quarterly basis on 1st May, 1st August, 1st November and 1st February based on the following, namely:-

Dearness Allowance release date	Quarterly average of Consumer Price Index points of the months	Applicable for the month
1 st May	January, February and March	May, June and July
1 st August	April, May and June	August, September and October
1 st November	July, August and September	November, December and January
1 st February	October, November and December	February, March and April

(d) there shall be no ceiling on Dearness Allowance;

(e) while working out quarterly average, only first two decimals will be considered.”;

(b) after sub-regulation(8), in the *Explanation*, for clause (b) the following shall be substituted, namely:-

“(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in clauses (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) to the *Explanation* to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for Dearness Allowance.”

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) On and from the 1st November, 2022,-

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.35 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:-

TABLE

S.No.	Place of work	House rent allowance
(1)	(2)	(3)
1.	Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	10.0 per cent. of Pay
2.	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	9.0 per cent. of Pay
3.	Other places	8.0 per cent. of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.35 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (3) of the above Table.

Note:- The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall be also be restricted to 150 per cent. of House Rent Allowance as hitherto.”.

7. For regulation 23 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“23.(1) On and from the 1st November, 2022, if an officer is serving in a place mentioned in Column (2) of the Table below, a city compensatory allowance at the rate specified in Column (3) thereof against that place shall be payable:

TABLE

S. No. (1)	Places (2)	Rate (3)
1.	Places in Area 1 and above and in the State of the Goa	Rs. 2300/- per month
2.	Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	Rs. 1900/- per month

(2) On and from the 1st November, 2022, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations:

Provided that where at any of the places indicated in column (1) of the Schedule, Hill and Fuel Allowance as provided under sub-regulation (10) is also payable, then the officer shall be eligible to draw only higher of the two allowances and not both.”;

Provided further that of such higher of the two allowances is less than the aggregate of Special Allowance and Hill and Fuel Allowance drawn by the Officer on 31st December, 1989 then such difference shall be protected as Personal Allowance till such time the Officer remains at that place.

(3) On and from the 1st November, 2017, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling under Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area

Compensatory Allowance at the rate of Rs. 600/- per month or Rs.525/- per month according to the classification of area as Group 'A' or Group 'B' respectively.

- (4) On and from the 1st April, 2024, if an officer is transferred from one place to another in the middle of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.2500/- per month per child with a maximum upto two children, from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year.

Provided that such allowance shall cease to be payable if all the children cease studying at the former place.

- (5) On and from the 1st April, 2024, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.7500/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where such officer is deputed to an organisation which is located at the same place or to the training establishment not owned by the Bank where he was posted immediately prior to his deputation or to the training establishment not owned by the Bank, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs. 3750/- per month:

Provided further that where an Officer is deputed to another office or branch within the same municipal limits or urban agglomeration, in Metro or Major A class cities where the distance of such deputation is twenty kilometers and more from the parent branch or office, he shall be eligible for halting allowance as provided in sub-regulation (4) of Regulation 41.

- (6) On and from the 1st April, 2024, if an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than four days at a time or an aggregate of four days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 15 per cent. of his Basic Pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only:

Provided that, where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorization of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorization takes effect.

- (7) On and from the 1st April, 2024, an officer shall be entitled for a closing allowance of Rs.1500/- per quarter for each of the closing.
- (8) On and from the 1st November, 2017,, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs. 300 per month.”.
- (9) If an officer is required to work as custodian of a vault or locker on a holiday, he shall be eligible for a Diem Allowance at the rate to which he is entitled.
- (10) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for the Hill and Fuel allowance as specified in the table below, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Place (2)	Rate (3)
1.	Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.1450/- per month
2.	Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.1900/- per month
3.	Place with an altitude of 3000 metres and above	5 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.3750/- per month;

(11) On and from 1st November, 2022, an officer shall be eligible for Learning Allowance of Rs 850/- per month along with Dearness Allowance thereon.

Note: Learning allowance with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, that is, Pension including Defined Contribution Pension Scheme (National Pension Scheme), Provident Fund and Gratuity.

(12) On and from the 1st November, 2022, an Officer shall be eligible for a fixed Location allowance of Rs.1200/- per month who are posted in areas other than the areas that are eligible for City Compensatory Allowance. This fixed allowance shall not be reckoned for payment of Dearness Allowance, superannuation benefits, viz, pension including Defined Contribution Pension Scheme(National Pension Scheme), Provident fund and Gratuity.

(13) (a) From the financial year 2023-24, Performance Linked Incentive shall be payable to all officer employees based on the metrics put in place by the Competent Authority of the Bank as per their priorities from the following select parameters, namely:

(i) Current Account Savings Account; (ii) Non-Performing Assets; (iii) Special Mention Accounts; (iv) Non – interest income; (v) Total Business; (vi) Profitability; (vii) Return on Assets or Return on Equity; (viii) Government Schemes.

(b) The Performance Linked Incentive amount shall be payable in 0-15 (maximum) number of days of pay (Basic + DA) depending on the metrics put in place by the Competent Authority as mentioned in clause (a) above.”.

8. In regulation 24 of the said regulations,-

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) On and from 1st November, 2022, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer’s own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Grade (2)	Maximum limit of reimbursement (3)
1.	Junior Management and Middle Management Grade	Rs.13000/- per annum or the amount incurred whichever is less
2.	Senior Management and Top Executive Grade	Rs.15400/- per annum or the amount incurred whichever is less

Note.1: An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Note.2: For the calendar year 2022, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2022 and December, 2022.”;

(b) after sub-regulation (3), following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) All officer employees shall also be eligible for reimbursement of Rs 500/- per year towards eye check-up.”.

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), on and from the 1st November, 2022, it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, a sum equal to 0.35 per cent. of the Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.075per cent of Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”

10. In Regulation 31 of the said regulations, following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that where the Sanctioning Authority refuses or postpones the leave of the Officer, it shall record the reasons for the same in writing.”.

11. In regulation 32 of the said regulations, sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(3) On and from 1st April, 2024, an officer employee shall be eligible to avail two days casual leave for half- a day on four occasions in a year, out of which two occasions shall be in the morning and two occasions in the afternoon:

Provided that casual leave under this category shall be availed after applying twenty-four hours in advance:

Provided further that at the time of carrying over the balance in casual leave to unavailed casual leave account, the fraction in the balance, if any, shall be ignored.”.

12. In regulation 33 of the said regulations:-

(a) for sub-regulation (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:

“(4) On and from 1st June, 2015, privilege leave may be accumulated upto not more than two hundred and seventy days, except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that on and from 1st April, 2024, encashment of privilege leave shall be restricted upto a maximum of two hundred fifty-five days:

Provided further that an Officer shall also be eligible for encashment of privilege leave at the rate of five days for each calendar year at the time of any festival of his choice and an Officer who have already completed fifty-five years of age and above shall be eligible to encash Privilege Leave at the rate of seven days for each calendar year till his retirement.

(5) An officer desiring to avail of Privilege Leave shall ordinarily give not less than ten days notice of his intention to avail of such leave except for the purpose of Leave Fare concession:

Provided that on and from the 1st April, 2024, no such advance notice of ten days shall be required for availing Privilege Leave for office bearers and Executive Committee members of a registered Trade Union.”;

(b) after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(7) On and from the 1st April 2024, for the purposes of calculating Privilege Leave, all types of leave availed except casual leave and mandatory leave shall be excluded.”.

13. In regulation 34 of the said regulations,-

(a) in sub-regulation (1), the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided that on and from 1st April, 2024, an officer shall be eligible for sick leave at the rate of one month for each year of service:

Provided further that the total number of sick leave (including Additional sick leave mentioned in Regulation 35) shall not exceed seven hundred and twenty days in the entire service of the officer.”;

(b) after sub-regulation (5), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(6) On and from the 1st April 2024, a single male parent employee may avail sick leave for the sickness of his children of eight years and below subject to production of medical certificate.

(7) On and from the 1st April 2024, a women employee may avail one day sick leave per month without production of medical certificate”.

(8) On and from the 1st April, 2024, officer employees may avail sick leave for the sickness of their Special Child of fifteen years and below for a maximum period of ten days in a calendar year subject to production of medical certificate”

(9) On and from the 1st April 2024, officer employees of age of fifty-eight years and above, may avail sick leave towards hospitalization of his or her spouse at a centre other than place of work for a maximum period of thirty days in a calendar year.”.

14. In regulation 36 of the said regulations, in sub-regulation (1),-

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) a female employee shall be eligible for maternity leave on substantive pay for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that in case of delivery of twins, the period of maternity leave shall be eight Months:

Provided further that on and from 1st April, 2024 in case of delivery of more than two children in one delivery, the period of maternity leave shall be twelve months:

Provided further that maternity leave may be availed combining with any other kind of leave except casual leave.”;

(b) For clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

“(d) female employee may avail leave once during service for legally adopting a child who is below one year of age, for a maximum period of nine months, subject to the following terms and conditions, namely:-

(i) leave will be granted for adoption of only one child.

(ii) the adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;

(iii) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy;

(iv) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service.”.

(c) after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(f) on and from the 1st April 2024, maternity leave may be availed for In vitro fertility (IVF) treatment subject to production of medical certificate within the overall limit of twelve months.

(g) on and from the 1st April 2024, Special maternity leave may be availed by a female employee upto sixty days in case of a still born or death of the infant within twenty-eight days of birth.”.

15. For regulation 37A of the said regulation, the following regulation shall be substituted, namely:-

“37 A. Special casual leave and special leaves.- (1) With effect from the 1st November, 2020, an officer employee shall be eligible for Special Casual Leave on occasions when the branch where the officer is working or the place where he is residing is affected by curfew, riots, prohibitory orders, natural calamities, floods, and the like.

- (2) With effect from the 1st November, 2020, a physically or orthopedically handicapped officer shall be eligible for four days special casual leave.

- (3) With effect from 1st April, 2024, Principal Officer bearers of All India Officers’ Unions or Associations shall be granted special leave upto twenty-five days in a calendar year.

- (4) With effect from 1st April, 2024, officers who are defense representatives in departmental enquiry, may avail one day special leave for the purpose of preparing the defense submission of an officer employee:

Provided that such special leave shall be availed for a maximum of ten occasions in a year.

- (5) An Officer may also be granted special casual leave and any special leave as may be decided by the Board in accordance with the guidelines of the Government.”.

16. After regulation 37 A of said regulations, the following shall be inserted, namely:-

“37 B. Bereavement leave.- An officer employee shall be granted bereavement leave on the demise of the family members (Spouse, children, parents and parents-in-law) for such number of days as may be decided by the Board from time to time:

Provided that the intervening holidays will form part of the leave:

Provided further that the said leave should be availed within a maximum period of fifteen days of the demise:

Provided further that the said leave shall not be considered as ‘Active service’ for the purpose of calculation of Privilege leave.”.

17. In regulation 41 of the said regulations,-

- (a) for sub regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) On and from 1st April 2024, wherever an Officer is required to travel on duty, the following provisions shall apply, namely:-

- (a) an officer in Junior Management Grade will be entitled to travel by AC 1st class by any train including Premium Trains like Rajdhani or Shatabdi or Tejas or Vande Bharat or Amrit Bharat, etc. (except luxury trains):

Provided that such officer may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

- (b) an officer in Middle Management Grade will be entitled to travel by AC 1st Class by any train including Premium Trains as mentioned in clause (a):

Provided that he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 500 kilometers:

Provided further that he may travel by air (economy class) even for shorter distance, if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

- (c) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by any train including premium trains (as mentioned in clause (a) above) or by air (economy class);
- (d) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed five hundred kilometers:

Provided that when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car;

- (e) any other officer may be authorized by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle;
- (f) an officer of any grade or scale shall be eligible to travel by water transport in deluxe cabin category between places not connected by road or air or rail;
- (g) an Officer shall be eligible for fare by premium trains (except luxury trains).

Note 1: Goods and Services Tax Charges levied on Train Fare shall be over and above the entitlement.

Note 2: In view of prevailing dynamic fare system, the cost of train tickets charged on the date of booking will be reimbursed.”;

- (b) in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) **Halting Allowance.**- On and from 1st April 2024, an officer in the grades or scales set out in column (2) of the Table shall be entitled to ‘*per diem*’ Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (3) thereof, namely:-

TABLE

S. No.	Grades or Scales of officers	Halting Allowance			
		Metro Rs.	Major 'A' Class cities Rs.	Area I Rs.	Other Places Rs.
(1)	(2)	(3)			
1.	Officers in Scale VI & above	4050	2925	2475	2150
2.	Officers in Scale IV & V	3375	2925	2475	2150
3.	Officers in Scale I, II and III	2925	2475	2150	1800

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.- For the purpose of computing Halting allowance, “*per diem*” shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “*per diem*” shall mean a period of not less than eight hours.

18. In regulation 42 of the said regulations,-

(a) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(3) On and from the 1st April, 2024, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Grade/Scale (2)	Amount (3)
1.	Senior Management and Top Executive (Officers in Scale IV and above)	Rs.50000/-
2.	Junior Management and Middle Management (Officers upto Scale III)	Rs.40000/-

(b) in sub-regulation (4), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:

“Provided that on and from the 1st April 2024, where no residential accommodation is made available by the Bank to an Officer at the new place of posting and where such an Officer may incur additional expenses in the process of taking over charge, for reasons beyond his control, the Competent Authority, from the date of joining of such officer at the new place, may on merits consider grant of either lodging and Boarding charges or (b) Halting Allowance for a

period of fifteen days or till the time the quarters are made available to him, whichever is earlier.”.

19. for regulation 44 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“44 (1) **Leave Travel Concession.-** (1) During each block of four years, an officer shall be eligible for Leave Travel concession for travel to his place of domicile once in each block of two years:

Provided that, he may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route:

(2) On and from from the 1st April, 2024, alternatively, an officer by exercising an option anytime during a four year block or two year block, as the case may be, surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to place of domicile) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 5,500 kilometers (one-way) for officers in Junior Management Grade Scale I, Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III and 6,500 kilometers (one-way) for officers in Senior Management Grade Scale IV and above:

Provided that an officer opting to encash his Leave Travel Concession, shall prefer the claim for himself and his family members only once during the block in which such encashment is availed of and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time-to-time:

Provided that with effect from the 1st April, 2024, an officer in Junior Management Grade Scale I, while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC 1st Class fare by train for the distance travelled, whichever is less, and the same rules shall apply when an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III avails Leave Travel Concession, where the distance is less than 500 kilometers.

(4) Once in every four years, when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his privilege leave not exceeding thirty days at a time or he may while travelling in one block of two years to his home town and in other block any place in India, be permitted encashment of privilege leave with a maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the leave travel concession is availed shall be admissible:

Provided that an officer at his option shall be permitted to encash one day additional privilege leave for donation to Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorising the bank to remit the amount to the fund.

- (5) Leave Travel concession can be availed independently where both husband and wife are working in the same Bank.
- (6) For employees working in North-east States, Leave Travel concession shall begin from Guwahati and the eligible train fare from their place of work to Guwahati shall be additionally paid.
- (7) The eligible fare for Andaman and Nicobar Islands to Chennai or Kolkata, Lakshadweep to Kochi, far-flung area branches in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jammu and Kashmir or any other areas which are not directly connected by train shall be additionally reimbursed under Leave Travel concession in addition to normal entitlement for the employees working in these areas to the nearest major Railway Station.
- (8) Leave Travel concession facility shall be allowed for an escort who accompanies an Officer with benchmark disabilities on the journey subject to following conditions, namely:
- (a) prior approval of the competent authority is obtained on each occasion;
 - (b) the nature of physical disability of the Officer is such as to necessitate an escort for the journey and in case of doubt, the decision of the head of the Department / Controller shall be final;
 - (c) the officer with such benchmark disabilities does not have an adult family member as dependent to accompany him;
 - (d) the officer with such benchmark disabilities and the escort shall avail of the concession if any, in the Rail or Bus fare as might be extended by Railways or State Roadways authorities in such cases; and
 - (e) any other person who is entitled to Leave Travel concession as dependent does not accompany the officer with such benchmark disabilities on the journey.
- (9) Where an officer has applied for Leave Travel concession or Leave in advance and has booked the tickets and the Leave Travel concession is declined or deferred by the management, the cancellation charges will be reimbursed by the Bank.
- (10) Where an officer has applied for Leave Travel concession or leave as per stipulated time and the same is sanctioned and when advance booking of train tickets is not possible, tickets purchased under Tatkal/Premium tatkal will be reimbursed.”.

20. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“ SCHEDULE

(SEE SUB-REGULATION (2) OF REGULATION 23)

On and from the 1st of November, 2022, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Special Area Allowance

Sl No.	Place	Allowances (in Rs.)	
		Pay below Rs.48,481/-	Pay above Rs. 48,481/-
1.	Mizoram		
	a) Chimpui district and areas beyond 25 kms from Lunglei	4100	5300
	Town in Lunglei district.		
	b) Entire Lunglei District excluding areas beyond 25 kms from Lunglei town	4100	5300
	c) Entire Aizawl District	2700	3400
2.	Nagaland	4100	5300
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	4100	5300
	b) South Andaman (including Port Blair)	4100	5300
4.	Sikkim	4100	5300
5.	Lakshadweep Islands	4100	5300
6.	Assam	1000	1200
7.	Meghalaya	1000	1200
8.	Tripura		
	a) Difficult areas of Tripura	4100	5300
	b) Throughout Tripura except Difficult areas	2700	3400
9.	Manipur	2700	3400
10.	Arunachal Pradesh		
	a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	4100	5300
	b) Throughout Arunachal Pradesh except Difficult areas	4100	5300
11. A	Union Territory of Jammu and Kashmir		
	1) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	4100	5300
	2) Udhampur District:		
	(a) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, Thakrakote and Nagote	4100	5300
	(b) All Areas in Mahore tehsil other than those included in (c) below	4100	5300

	(c) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from keasi side in Tehsil Mohre	4100	5300
	3) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kashmir Tehsil	4100	5300
	4) Baramulla District:		
	(a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar sub-division and Keran Illaqua	4100	5300
	(b) Matchill	4100	5300
	5) Poonch and Rajouri District: Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts	2700	3400
	6) Areas not included in (1) to (5) above, but which are within the distance of eight kms. from the Line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for Border Allowance from time to time by the State Government for their own staff.	2700	3400

B	Union territory of Ladakh: Leh District: Noyama and Nobre Zaskar All other places in the District	4100	5300
12	Himachal Pradesh		
	(1) Chamba District		
	a) Pangti Tehsil, Following Panchayats and villages in Bharmour Tehsil: Panchayats: Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tunda Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	4100	5300
	b) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and villages included in (a) above	4100	5300
	c) Jhandru Panchayat in Bhartiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper)	2700	3400
	2) Kinnaur District		
	a) Asrang, Chitkul and Hango Kuno or Charang Panchayats, 15/ 20 area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat areas specified above	4100	5300
	b) Entire district other than areas included in (a) above	4100	5300
	3) Kullu District		

	a) 15/20 area of Nirmand tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	4100	5300
	b) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burao of Tehsil Nirmand)	2700	3400
	4) Lahaul and Spiti District: Entire area of Lahaul and Spiti	4100	5300
	5) Shimla District		
	a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chandi-Branda	4100	5300
	b) Dodra-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghor Chaibis of Pargana Sarahan	4100	5300
	c) (I) Chopal Tehsil (i) Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan; (ii) Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area; (iii) Pargana Barabis; and	2700	3400

	(iv) Kasba Rampur and Ghor Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, (II) Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu)		
	(6) Kangra District:		
	(a) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	4100	5300
	(I) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town: a) Women's ITI, Dari, b) Mechanical Workshop, Ramnagar, c) Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, d) CRSF Office at lower Sakoh, e) Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, f) HRTC Workshop, Sadher, g) Zonal Malaria Office, Dari, h) Forest Corporation Office, Shamnagar, i) Tea Factory, Dari, j) I.P.H. Sub- Division, Dari k) Settlement Office, Shamnagar, l) Binwa Project, Shamnagar,	2700	3400

	(II) Palampur Town, including Himachal Pradesh Krishi hvavidyalaya Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included Palampur Town- (a) H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus, (b) Cattle Development Officer or Jersey Farm, Banuri, (c) Sericulture Officer or Indo-German Agriculture (d) Workshop or HPPWD Division, Bundla, (e) Electrical Sub-Division, Lohna, (f) D.P.O. Corporation, Bundla, (g) Electrical HPSE Division, Ghuggar		
	(7) Mandi District:		
	Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in Thunag Tehsil: Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjheli, Jaryar, Johar Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Following Panchayats of Dharampur Block: Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja	2700	3400
	(8) Sirmaur District: a) Following Panchayats of i) Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil),	2700	3400
	ii) Bharog Bheneri (Paonta Tehsil), iii) Birla (Nahan Tehsil), iv) Dibber (Pachhad Tehsil) and v) Thana Kasoga (Nahan Tehsil) b) Thansgiri Tract		
	(9) Solan District: Mangal Panchayat.	2700	3400
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above	1000	1200
13.	Uttarakhand: Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts	4100	5300

14.	West Bengal: South 24 Parganas District Sunderban Areas (south of Dampier Hodge's line), namely, Bhagatush Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhinga Khali, Sajnakhali, Gosaba, Amlamathi (Bidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi, Bhanchi, Pathar Pratima, Bhagabatpur, Saptamukhi, Namkhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mousini, Kalinagar, Haroa, Hingalganj, Basanti, Kuemari, Kultola, Ghushighata (Kulti)	1000	1200.”.
-----	---	------	---------

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member Banks on the basis of specific mandate given by the respective Banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

SUMESH KUMAR, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./215/2026-27]